

विभिन्न संवैधानिक निकाय



भारतीय संविधान की अनुसूचियां:



भारतीय संविधान में संवैधानिक निकाय

एक संवैधानिक निकाय या संस्था वह है जो संविधान के विशेष वाक्य में विशेष रूप से उल्लिखित हो मूल रूप से या कुछ संशोधन के आधार पर, जबकि एक गैर-संवैधानिक निकाय वह है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है।

चुनाव आयोग

1. संविधान भाग XV के अनुच्छेद 324 में वर्णित चुनाव आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है।

- वर्तमान में चुनाव आयोग की संस्था में मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- वे **छह साल** की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। सेवानिवृत्ति की आयु **65 वर्ष होती है**, जो भी पहले आए।
- भारत के पहले चुनाव आयुक्त **सुकुमार सेन** थे।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

- संविधान के **भाग XIV** में अनुच्छेद **315 से 323** के तहत उल्लेख किया गया (अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख करता है)।
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं।
- इनका कार्यकाल **छह वर्ष का होता है** और सेवानिवृत्ति की आयु **65 वर्ष होती है**, जो भी पहले हो।
- UPSC का अध्यक्ष (पदभार ग्रहण करने पर रोक) भारत सरकार या किसी राज्य में आगे रोजगार के लिए योग्य नहीं है।

राज्य लोक सेवा आयोग

- राज्य लोक सेवा आयोग में राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं।
- पद का कार्यकाल 6 वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, जो भी पहले प्राप्त हो। वे अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं।
- अध्यक्ष और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, हालांकि वे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पद से हटाने के लिए समान प्रक्रिया अपनाई जाती है जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के लिए होती है।
- नोट** - संविधान के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग (JPSC) की स्थापना का प्रावधान भी है।
- एक जेपीएससी (JPSC) यूपीएससी (UPSC) और एसपीएससी (SPSC) के विपरीत, संबंधित राज्यों के अनुरोध पर संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया जा सकता है। इसलिए, जेपीएससी एक वैधानिक निकाय है जो संवैधानिक नहीं है।
- जेएसपीएससी (JPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कार्यालय का कार्यकाल फिर से छह वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, जो भी पहले हो।

वित्त आयोग

1. भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 280** में एक वित्त आयोग का प्रावधान है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर पांचवें वर्ष या समय से पहले गठित किया जा सकता है जब वह आवश्यक समझे।
2. वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। वे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करते हैं। वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं।
3. यह प्रमुख रूप से एक सलाहकार निकाय है और यह केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों की शुद्ध आय के वितरण और राज्यों के बीच आवंटन के आधार पर इस तरह के आय के हिस्सों के आवंटन की सलाह देता है।
4. पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष **के.सी. नियोगी थे** और वर्तमान में यह 15^{वाँ} वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष **एन के सिंह** हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 338-A में उल्लेख किया गया।

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

- संविधान के **भाग XVII** के **350-B** में इसका उल्लेख है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)

1. भारत का संविधान (**अनुच्छेद 148**) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है।
2. वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख होता है।
3. वह **जनता के धन का संरक्षक होता है** और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है।
4. यही कारण है कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कहा कि सीएजी(CAG) **भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा।**
5. सीएजी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके अधिकार और मुहर के तहत एक वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है।

6. वह **छह वर्ष** या **65 वर्ष** की आयु तक , जो भी पहले हो, के लिए कार्यालय सँभालते है।
7. उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही है।
8. केंद्र या राज्य सरकार स्तर पर सेवानिवृत्त होने या हटाए जाने के बाद वह कोई और रोजगार पाने के हकदार नहीं है।
9. सीएजी (CAG) के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, उस कार्यालय में सेवारत व्यक्तियों के सभी वेतन, भत्ते और पेंशन सहित, भारत की संचित निधि से वसूला जाता है। इस प्रकार, वे संसद के वोट के अधीन नहीं हैं।
10. वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और विधान सभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से संबंधित सभी खर्चों की लेखा परीक्षा करता है।
11. वह भारत की आकस्मिकता निधि और भारत के लोक निधि के साथ-साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य की लोक निधि से संबंधित सभी खर्चों की लेखा परीक्षा करता है।
12. वह केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट (लेखा परीक्षा) रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो संसद के दोनों सदनों (**अनुच्छेद 151**) के समक्ष रख सकते हैं।
13. वह किसी राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट(लेखा परीक्षा) रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपता है, जो बदले में, उन्हें राज्य विधायिका (**अनुच्छेद 151**) के समक्ष रखता है।
14. राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष CAG द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत करता है। लोक लेखा समिति फिर उनकी जाँच करती है और संसद में निष्कर्षों को प्रस्तुत करती है।

भारत के महान्यायवादी

1. भारत के संविधान के **अनुच्छेद 76** में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है।
2. पद के अनुसार यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
3. **राष्ट्रपति** द्वारा नियुक्त किया जाता है।
4. भारत का महान्यायवादी (AGI) वह हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो।
5. कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है।
6. अपने आधिकारिक कर्तव्यों में, महान्यायवादी को भारत के सीमा क्षेत्र में सभी अदालतों में उपस्थिति का अधिकार है। इसके अलावा, उसे संसद के दोनों सदनों या उनके संयुक्त बैठक और

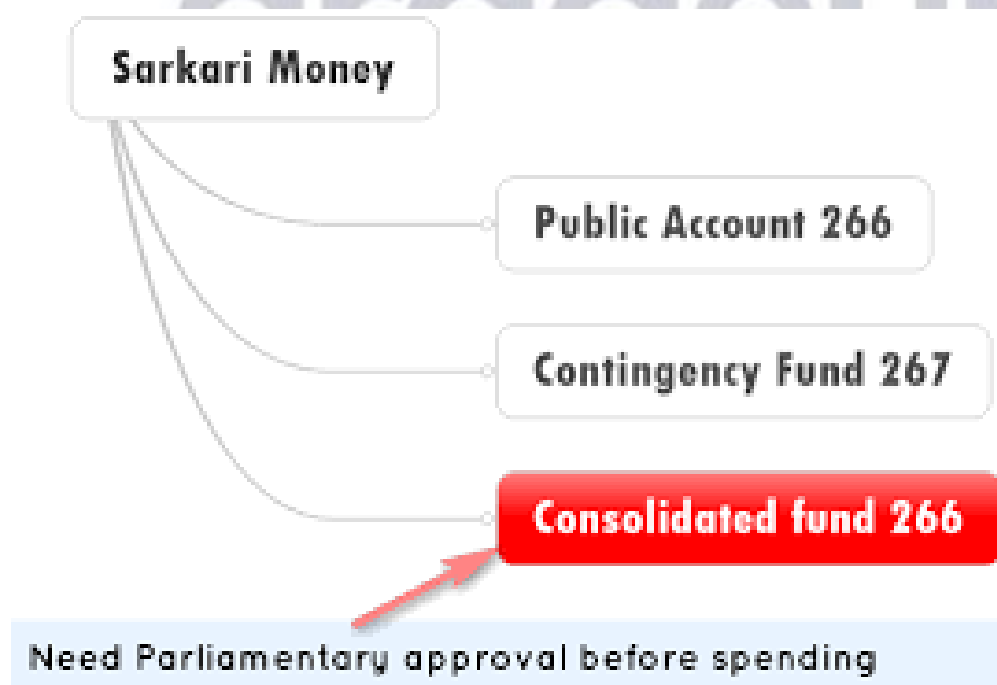
संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है और संसद की किसी भी समिति का भाग हो सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार के बिना। वह उन सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं का आनंद लेता है जो संसद सदस्य के लिए उपलब्ध होती हैं।

7. **नोट-** महान्यायवादी के अलावा, भारत सरकार के अन्य कानून अधिकारी भी होते हैं। वे भारत के सॉलिसिटर जनरल और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं। वे अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों की पूर्ति में महान्यायवादी की सहायता करते हैं। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविधान द्वारा केवल महान्यायवादी का कार्यालय बनाया गया है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 76 में महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।
8. भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले महान्यायवादी **मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाड** थे।

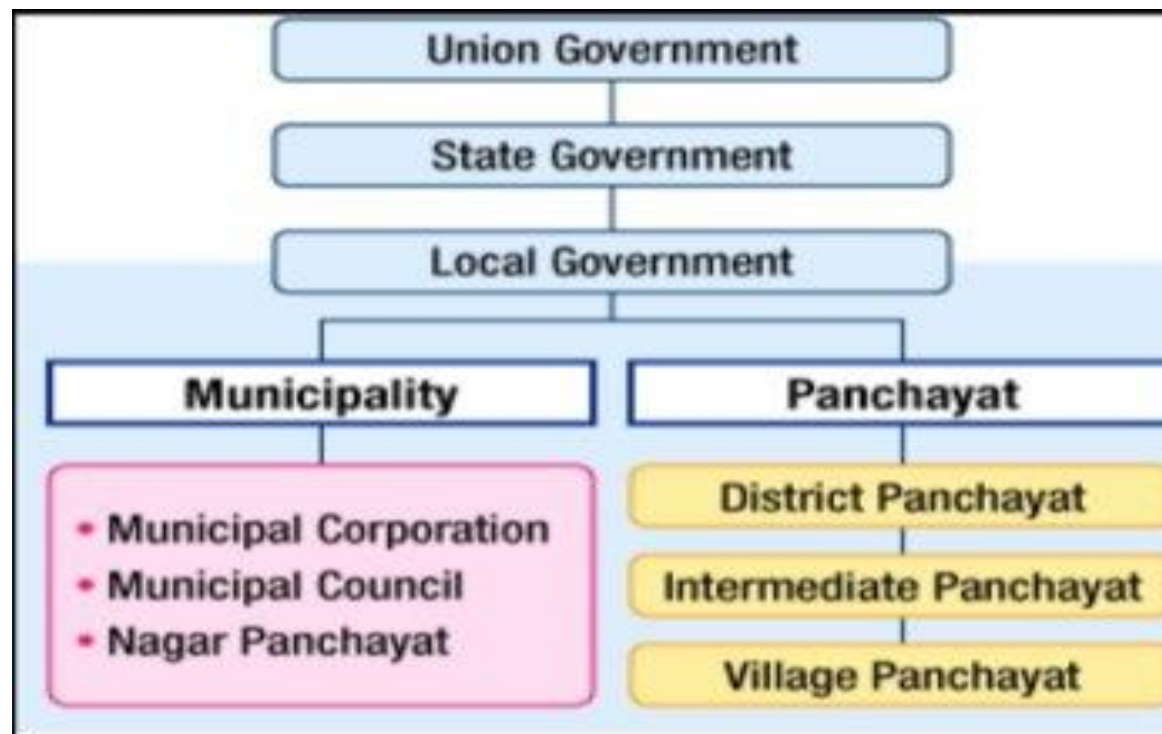
राज्य के महाधिवक्ता

1. संविधान (**अनुच्छेद 165**) में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के कार्यालय का प्रावधान किया गया है। वह राज्य का सर्वोच्च विधि या कानूनी अधिकारी होगा। इस प्रकार वह भारत के महान्यायवादी से मेल खाता है।
2. महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो।

भारतीय संविधान में धन:



भारत में स्थानीय सरकार



स्थानीय स्वशासन से संबंधित अनुच्छेद

Structure of Local Governments

- 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 (Part IX – Article 243 A to O) – 3 tier Panchayati Raj Institutions for rural areas
 - Zila Panchayat (District)
 - Intermediary Panchayat (Block/ Mandal/ Taluk)
 - Gram Panchayat (Village/ Cluster of Villages)
- 74th CAA of 1992 (Part IXA – Article 243 P to 243 ZG) – 3 types of ULBs
 - Municipal Corporations
 - Municipal Councils
 - Nagar Panchayats

SCHEDULES OF INDIAN CONSTITUTION:



CONSTITUTIONAL BODIES IN THE INDIAN CONSTITUTION

A constitutional body or an institution is the one which is specifically mentioned in the text of the constitution either originally or by virtue of some amendment, whereas a non-constitutional body is the one which isn't mentioned in the text of the constitution.

ELECTION COMMISSION

1. **Article 324** of the Constitution mentions about the election commission mentioned in **part XV**.
2. The institution of Election Commission presently consists of the chief election commissioner and two other election commissioners, appointed by the President.
3. They hold office for a term of **six years**. The age of retirement is **65 years**, whichever comes earlier.
4. The first election commissioner of India was **Sukumar Sen**.

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

1. Mentioned under articles **315 to 323** in **Part XIV** of the Constitution (Article 315 mentions about the public service commission for the union and the states).
2. The UPSC consists of a chairman and other members appointed by the president of India.
3. The term is of **six years** or the retirement age is **65 years**, whichever is earlier.
4. The chairman of UPSC (on ceasing to hold office) is not eligible for further employment in the Government of India or a state.

STATE PUBLIC SERVICE COMMISSION

1. A State Public Service Commission consists of a chairman and other members appointed by the governor of the state.
2. The term of office is 6 years or retirement age is 62 years, whichever is attained earlier. They offer their respective resignations to the governor.
3. The chairman and members can be removed only by the President, though they're appointed by the Governor. The ground for removal is same as that of a chairman or a member of the UPSC.
4. **NOTE** - There is a provision for the establishment of a Joint Public Service Commission (JPSC) for two or more states under the constitution.

5. A **JPSC** is/can be created by an act of parliament on the request of the respective states, unlike UPSC and SPSC which are constitutional bodies. Hence, a JPSC is a statutory body not a constitutional one.
6. The chairman and members of a JSPSC are appointed by the president. The term of office is again six years or the age of retirement is 62 years, whichever comes earlier.

FINANCE COMMISSION

1. **Article 280** of the Constitution of India provides for a Finance Commission. It is constituted by the president of India every fifth year or at such earlier time as he considers necessary.
2. The Finance Commission consists of a chairman and four other members to be appointed by the president. They hold office for such period as specified by the president in his order. They are eligible for reappointment.
3. It is majorly an advisory body though and it advises on the distribution of net proceeds of taxes to be shared between the centre and the states and the allocation between the states the respective shares of such proceeds.
4. The Chairman of the first finance commission was **K.C Neogi** and presently it is the 15th F.C whose chairman is **N.K Singh**.

NATIONAL COMMISSION FOR SCs

- Mentioned in Article 338 of the Constitution of India.

NATIONAL COMMISSION FOR STs

- Mentioned in Article 338-A of the Constitution of India.

SPECIAL OFFICER FOR LINGUISTIC MINORITIES

- It is mentioned in **350-B** in **Part XVII** of the Constitution.

COMPTROLLER and AUDITOR GENERAL of INDIA

1. The Constitution of India (**Article 148**) provides for an independent office of the Comptroller and Auditor General of India (CAG).
2. He is the head of the Indian Audit and Accounts Department.
3. He is the **guardian of the public purse** and controls the entire financial system of the country at both the levels—the Centre and the state.
4. This is the reason why Dr. B R Ambedkar said that the CAG shall be the **most important Officer under the Constitution of India**.
5. The CAG is appointed by the president of India by a warrant under his hand and seal.
6. He holds office for a period of **six years** or up to the age of **65 years**, whichever is earlier.
7. He can be removed by the President either on the grounds of proven misbehavior or incapacity. The method of removal is the same as that of a judge of the Supreme Court.
8. He is not entitled to hold any further employment after he retires or is removed, either at the center or at the state government level.
9. The administrative expenses of the office of the CAG, including all salaries, allowances, and pensions of persons serving in that office are charged upon the Consolidated Fund of India. Thus, they are not subject to the vote of Parliament.
10. He audits the accounts related to all expenditure from the Consolidated Fund of India, consolidated fund of each state and consolidated fund of each union territory having a Legislative Assembly.
11. He audits all expenditure from the Contingency Fund of India and the Public Account of India as well as the contingency fund of each state and the public account of each state.
12. He submits his audit reports relating to the accounts of the Centre to President, who shall, in turn, place them before both the Houses of Parliament (**Article 151**).
13. He submits his audit reports relating to the accounts of a state to the governor, who shall, in turn, place them before the state legislature (**Article 151**).

14. The President lays the reports submitted by CAG before both the Houses of Parliament. The Public Accounts Committee then scrutinizes them and reports the findings to the Parliament.

ATTORNEY GENERAL OF INDIA

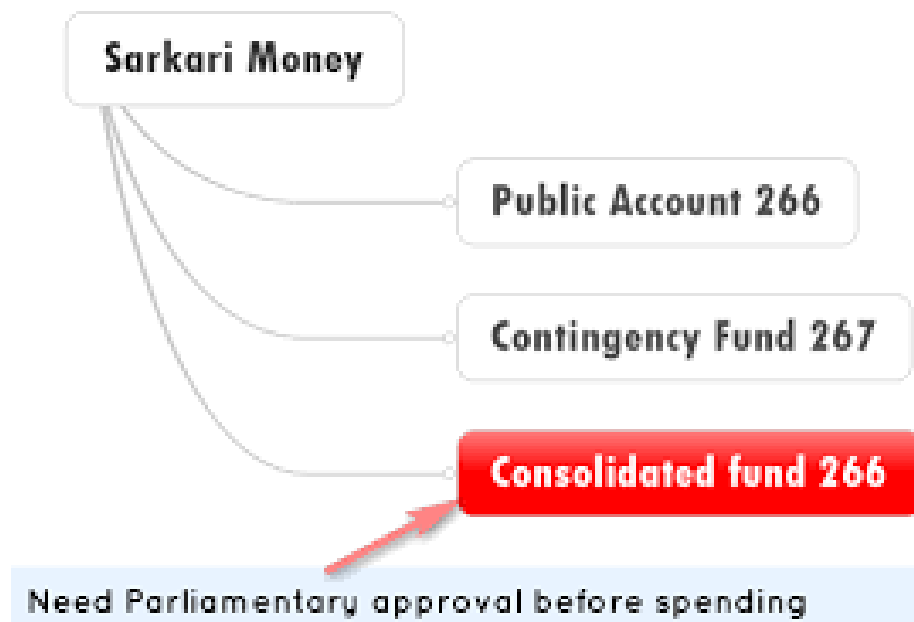
1. Mentioned in **Article 76** of the Constitution of India.
2. Titled as the highest law officer in the country.
3. Appointed by the **President**.
4. An AGI is one who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court.
5. The term is not fixed and he holds office during the pleasure of the President.
6. In the performance of his official duties, the Attorney General has the right of audience in all courts in the territory of India. Further, he has the right to speak and to take part in the proceedings of both the Houses of Parliament or their joint sitting and any committee of the Parliament of which he may be named a member, but without a right to vote. He enjoys all the privileges and immunities that are available to a Member of Parliament.
7. **NOTE-** In addition to the AG, there are other law officers of the Government of India. They are the solicitor general of India and additional solicitor general of India. They assist the AG in the fulfillment of his official responsibilities. It should be noted here that only the office of the AG is created by the Constitution. In other words, Article 76 does not mention about the solicitor general and additional solicitor general.
8. The first and the longest serving AGI of India was **Motilal Chimanlal Setalvad**.

ADVOCATE GENERAL OF THE STATE

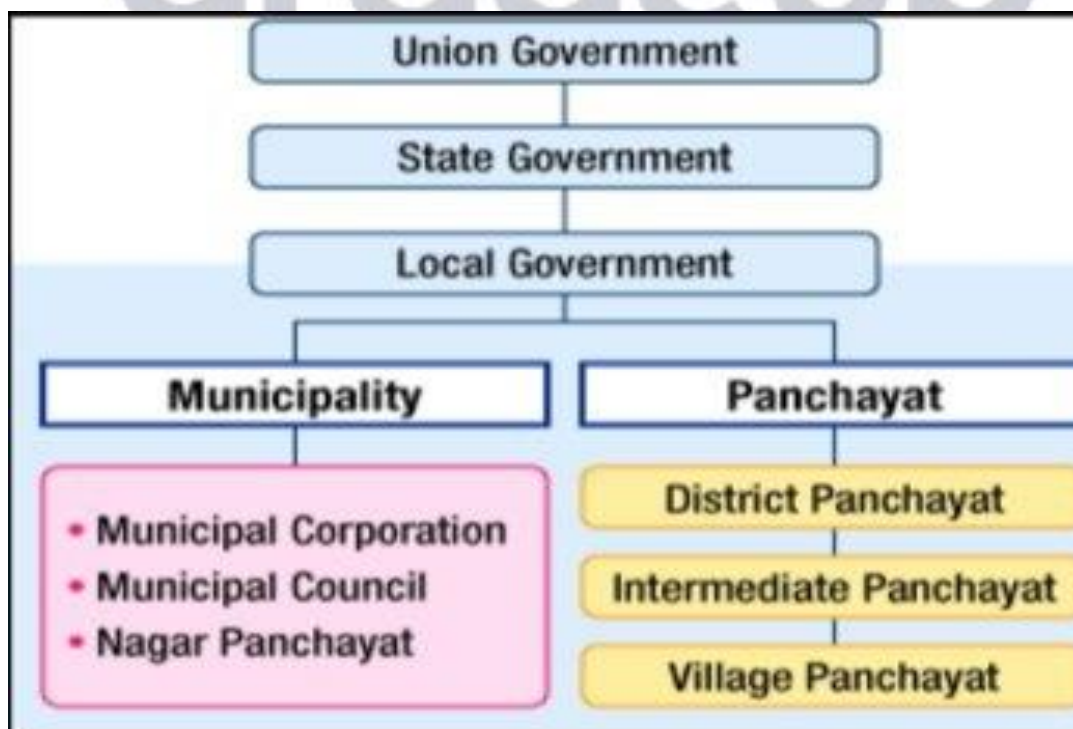
1. The Constitution (**Article 165**) has provided for the office of the advocate general for the states. He is the highest law officer in the state. Thus he corresponds to the Attorney General of India.

- The advocate general is appointed by the governor. He must be a person who is qualified to be appointed a judge of a high court.

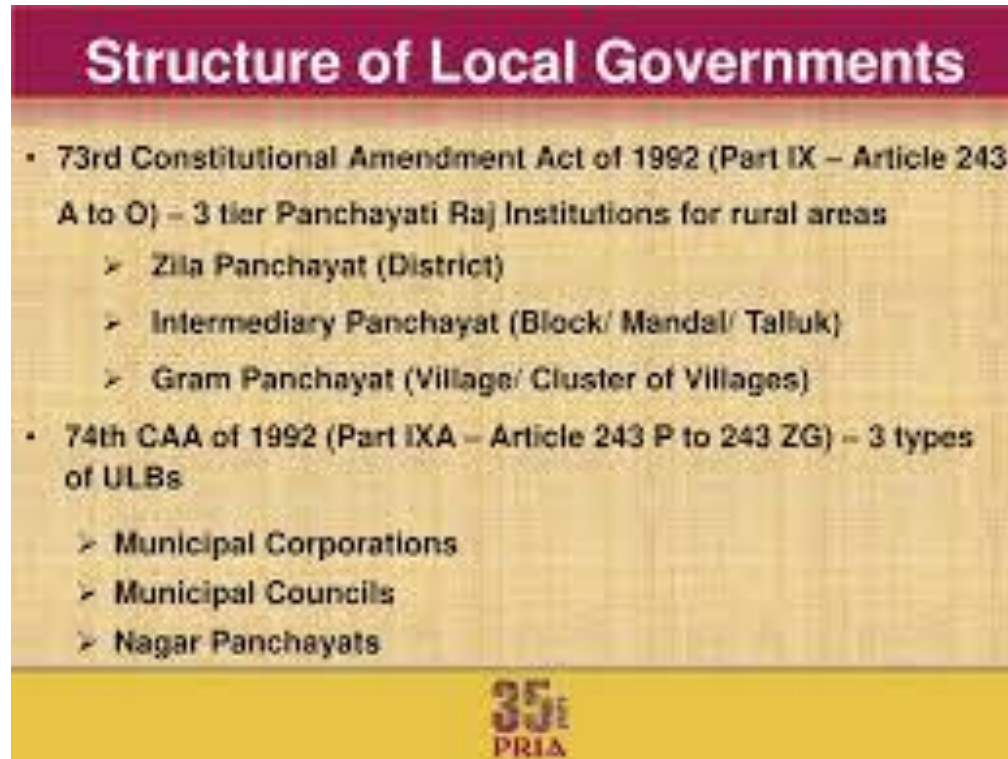
FUNDS IN INDIAN CONSTITUTION:



LOCAL GOVERNMENT IN INDIA



The Articles Related To The Local Self Government



Structure of Local Governments

- 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 (Part IX – Article 243 A to O) – 3 tier Panchayati Raj Institutions for rural areas
 - Zila Panchayat (District)
 - Intermediary Panchayat (Block/ Mandal/ Taluk)
 - Gram Panchayat (Village/ Cluster of Villages)
- 74th CAA of 1992 (Part IXA – Article 243 P to 243 ZG) – 3 types of ULBs
 - Municipal Corporations
 - Municipal Councils
 - Nagar Panchayats

35th PRIA

gradeup